RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 278
दि. 09.02.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम, डोभाल और कनाडा एनएसए के बीच बनी सहमति

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल की ओटावा यात्रा के दौरान, भारत और कनाडा सुरक्षा तथा कानून प्रवर्तन संपर्क अधिकारियों की स्थापना पर सहमत हुए हैं।अजीत डोभाल ने अपनी कनाडाई समकक्ष नथाली ड्रौइन के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता की है। इस बैठक से स्पष्ट संकेत मिला है कि हिंसक चरमपंथी समूहों को अब कनाडाई सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं है ।

डोभाल कनाडा की दो दिवसीय यात्रा पर थे, जहाँ उन्होंने कनाडाई प्रधानमंत्री की उप-क्लर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा व खुफिया सलाहकार नथाली ड्रौइन से मुलाकात की। यह बैठक भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से चले आ रहे नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा संवाद का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य आपसी सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है।

विदेश मंत्रालय (MEA) की विज्ञप्ति अनुसार, ठरअ की दो दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों पक्ष अपने कामकाजी संबंधों को बढ़ाने पर सहमत हुए, जो द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता का नियमित हिस्सा है।

भारत-कनाडा संबंधों में दिखा स्पष्ट "रीसेट"

सूत्रों के अनुसार, हाल ही में हुई भारत-कनाडा वाताओं से द्विपक्षीय संबंधों में एक स्पष्ट "रीसेट" देखने को मिला है। बातचीत के दौरान कनाडा की ओर से यह कड़ा संदेश दिया गया कि खालिस्तान-समर्थक नेटवर्क जैसे हिंसक चरमपंथी समूहों को अब कनाडाई सरकार का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। यह बदलाव भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर कनाडा के राजनीतिक रुख से कानून-प्रवर्तन आधारित कार्रवाई की ओर संकेत करता है।

खुफिया जानकारी साझा करना रहा मुख्य फोकस

सूत्रों ने बताया कि इन वाताओं का मुख्य केंद्र नशीले पदार्थों, साइबर खतरों और चरमपंथ से जुड़ी वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा करना था। विशेष रूप से खालिस्तान से जुड़े समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों ने माना कि ऐसे नेटवर्क अब केवल वैचारिक आंदोलन नहीं, बल्कि संगठित अपराध के रूप में काम कर रहे हैं।

संयुक्त कार्य योजना पर बनी सहमति

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों देशों ने अपने-अपने नागरिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए की गई पहलों में हुई प्रगति को स्वीकार किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-प्रवर्तन से जुड़े मुद्दों पर सहयोग को दिशा देने के

लिए एक साझा कार्य योजना पर भी सहमति बनी, जिससे व्यावहारिक स्तर पर सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला

बैठक में यह भी तय किया गया कि भारत और कनाडा सुरक्षा एवं कानून-प्रवर्तन संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। इससे द्विपक्षीय संचार को सुव्यवस्थित करने और नशीले पदार्थों-विशेष रूप से फेंटानिल के पूर्वरूपों-के अवैध प्रवाह तथा अंतरराष्ट्रीय संगठित आपराधिक नेटवर्कों पर समय पर जानकारी साझा करने में मदद मिलेगी।

साइबर सुरक्षा और डेटा साझाकरण पर जोर

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कनाडा की नथाली ड्रौइन ने साइबर सुरक्षा नीति और साइबर खतरों से जुड़ी सूचनाओं के औपचारिक आदान-प्रदान के लिए सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा, धोखाधड़ी और आव्रजन प्रवर्तन से जुड़े मामलों में सहयोग जारी रखने पर भी सहमति बनी।

प्रवासी समुदायों में चरमपंथ पर चिंता

डोभाल ने प्रवासी समुदायों के भीतर चरमपंथी धन उगाही, डराने-धमकाने और दुष्प्रचार का मुद्दा भी उठाया। सूत्रों के अनुसार, ये गतिविधियां मादक पदार्थों से होने वाली कमाई, दस्तावेजों की धोखाधड़ी और जबरदस्ती से जुड़ी हैं तथा सीधे तौर पर भारत को निशाना बनाती हैं।

साइबर माध्यमों और आव्रजन खामियों का दुरुपयोग

सरकारी सूत्रों ने बताया कि चरमपंथी समूह ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग भर्ती, कट्टरता और धन उगाही के लिए कर रहे हैं। इसके साथ ही वे आव्रजन प्रणाली की खामियों का फायदा उठाकर जांच से बचने या अपने गुर्गों को स्थानांतरित करने की कोशिश करते हैं, जिससे समन्वित साइबर नीति और डेटा साझाकरण दोनों देशों के लिए अहम हो गया है।

सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री से भी हुई अहम मुलाकात

अपनी यात्रा के दौरान अजीत डोभाल ने कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी आनंदसंगारी से भी मुलाकात की। इस बैठक को भारत-कनाडा संबंधों को बेहतर बनाने की ओटावा की तत्परता के स्पष्ट संकेत के रूप में देखा जा रहा है। कनाडाई सरकार अब यह मानने को तैयार है कि विदेश से निर्देशित हिंसक चरमपंथ केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा का मुद्दा है।

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले सप्ताह में भारत की संभावित यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक के अनुसार, इस दौरे के दौरान यूरेनियम, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री की मलेशिया में व्यापार प्रमुखों के साथ बैठक

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मलेशिया के चार प्रमुख उद्योगपतियों से बातचीत की। उन्होंने पेट्रोनास के अध्यक्ष और समूह सीईओ तन श्री तेंग्कू मुहम्मद तौफिक; बरजाया कॉर्पोरेशन बरहाद के संस्थापक तन श्री दातो सेरी विंसेंट तन ची यिउन; खजानाह नेशनल बरहाद के प्रबंध निदेशक दातो अमीरुल फैसल वान जाहिर; और फि सन इलेक्ट्रॉनिक्स के संस्थापक दातो पुआ खेन सेंग से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री ने भारत और मलेशिया के बीच बढ़ते व्यापार-से-व्यापार संबंधों और भारतीय विकास गाथा में मलेशियाई कंपनियों की गहरी रुचि की सराहना की। उन्होंने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने और एक स्थिर, कुशल और पूवार्नुमानित व्यापार एवं नीतिगत वातावरण बनाने के लिए हाल के वर्षों में भारत में की गई पहलों और सुधारों का उल्लेख किया। उन्होंने मलेशियाई व्यवसायों को विशेष रूप से अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वास्थ्य सेवा आदि क्षेत्रों में भारत द्वारा प्रदत्त अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री ने 7 फरवरी 2026 को कुआला-लंपुर में आयोजित होने वाले 10वें भारत-मलेशिया सीईओ फोरम की सराहना की और आशा व्यक्त की कि इन चचाओं से भारत-मलेशिया व्यापार और निवेश संबंधों को और अधिक मजबूती मिलेगी।

उद्योग जगत के प्रमुखों ने भारत सरकार द्वारा विकसित भारत के निर्माण की दिशा में किए गए सुधारों की प्रशंसा की और भारत की विकास गाथा में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने अपने निवेश पोर्टफोलियो का विस्तार करके और भारतीय समकक्षों के साथ संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं को तलाशकर भारत में अपनी व्यावसायिक उपस्थिति बढ़ाने में गहरी रुचि दिखाई।

'मेरी हत्या कराना चाहते हैं मुकेश रौशन, पीएम से मिलूंगा', तेज प्रताप का सनसनीखेज आरोप, 5 जयचंदों का बताया नाम

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पटना में एक प्रेस वार्ता के दौरान कई गंभीर

आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें घर से निकालने और उनकी छवि को धूमिल करने में "जयचंदों" का हाथ है। यादव ने इस मामले में पूर्व विधायक मुकेश रौशन, संजय यादव, रमीज, शक्ति सिंह और सुनील सिंह का नाम लिया है।

'छत्तीसगढ़ @ 25 : शिफ्टिंग द लेंस' पुस्तक पर आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में साप्ताहिक पत्र 'ऑर्गेनाइजर' के 'भारत प्रकाशन' द्वारा प्रकाशित 'छत्तीसगढ़ @ 25 : शिफ्टिंग द लेंस' पुस्तक पर आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

श्री अमित शाह ने कहा कि ऑर्गेनाइजर हमेशा से अंग्रेजी पत्रकारिता में मूल भारत का विचार रखता आया है, उस पर दृढ़ रहा है और उसके अनेक आयामों को भारतीय जनता के सामने रखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में आज उँ३३२१ँ @ 25: ग्रँ३ल्लॅ ३ौ छील्लर का सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता विषय पर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि

सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता शब्द किसी भी राष्ट्र या राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जिसकी रचना आजादी के बाद हुई, उसके लिए और अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने निर्णय किया कि छोटे राज्यों का प्रयोग सिर्फ प्रयोग मात्र नहीं है बल्कि वहां की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी के समय एक साथ झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की रचना का निर्णय किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सफल होने से ही संपूर्ण विश्व स्थिर और समृद्ध होगा, यह आज पूरे विश्व ने स्वीकार किया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि अटल जी के कार्यकाल के दौरान बने नए राज्यों में किसी भी प्रकार का मनमुटाव उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन केन्द्र में पिछली सरकार के दौरान बनने वाले एक नए राज्य तेलंगाना के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में बहुत अधिक कटुता हो गई जो एक दशक से भी अधिक समय तक चली। उन्होंने कहा कि आज भी दोनों राज्यों के बीच कई विवाद लंबित हैं।

वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए उमड़ी भीड़, एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम, वीडियो जमकर हुआ वायरल

भारतीय क्रिकेट के भविष्य ने एक बार फिर दुनिया को अपना लोहा मनवा दिया है।

जिम्बाब्वे की धरती पर अंडर-19 विश्व कप 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय टीम आज जब मुंबई एयरपोर्ट पहुंची, तो वहां का नजारा किसी त्योहार से कम नहीं था।

हाथों में तिरंगा, ढोल-नगाड़ों की थाप और 'वर्ल्ड चैंपियंस' के नारों के साथ फैंस ने अपने इन युवा सितारों का पलक-पावड़े बिछाकर स्वागत किया। करीब एक महीने तक चले कड़े संघर्ष के बाद छठी बार 'विश्व विजेता' का टैग लेकर लौटे इन खिलाड़ियों के चेहरे पर जीत की चमक साफ देखी जा सकती थी। एयरपोर्ट के एग्जिट गेट पर जैसे ही कप्तान आयुष म्हात्रे सोने जैसी चमकती वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर बाहर निकले, फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया।

प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर, सीतापुर दो दिन के लिए 'नो-फ्लाइंग जोन' घोषित

(जीएनएस)।

सीतापुर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में 9 फरवरी सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने जिले को दो दिनों के लिए नो-फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। यह आदेश रविवार से प्रभावी होकर सोमवार शाम कार्यक्रम के समापन तक लागू रहेगा।

नो-फ्लाइंग जोन के तहत जिले की सीमा में ड्रोन उड़ाने, गुब्बारे छोड़ने और पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंध के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर के लोनियनपुरवा अंतर्गत शास्त्री नगर कॉलोनी स्थित तपोधाम आश्रम में आयोजित गोरखनाथ प्रतिमा स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने 9 फरवरी को आ रहे हैं। कार्यक्रम स्थल घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

शनिवार देर शाम आईजी जोन लखनऊ किरण एस ने स्वयं कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए सभी इंतजाम समय से पूरे करने के निर्देश दिए।

हरिहरा गांव में तस्करी के लिए गौवंश ले जा रही बोलेरो हादसे का शिकार ये खबर भी पढ़े : हरिहरा गांव में तस्करी के लिए गौवंश ले जा रही बोलेरो हादसे का शिकार

मुख्यमंत्री के आगमन के लिए जीआईसी मैदान में हेलीपैड तैयार कराया गया है। यहां से कार्यक्रम स्थल तक करीब दो किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जिससे मुख्यमंत्री का काफिला सुरक्षित रूप से कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सके।

अमरावती क्वांटम सेंटर की आधारशिला रखी गई

(जीएनएस)।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के अमरावती में अमरावती क्वांटम वैली के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए घोषणा की कि "यह केवल एक इमारत की आधारशिला नहीं है, बल्कि भारत के क्वांटम भविष्य की आधारशिला है।"

क्वांटम प्रौद्योगिकी को एक विकल्प के बजाय एक रणनीतिक आवश्यकता बताते हुए, मंत्री महोदय ने कहा कि यदि भारत आने वाले दशकों में अपनी संचार प्रणालियों, रक्षा वास्तुकला, स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित करना चाहता है तो उसके पास इस क्षेत्र में नेतृत्व करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

नवाचार और वैश्विक तकनीकी स्थिति

अमरावती क्वांटम वैली के शिलान्यास समारोह में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और शिक्षा राज्य मंत्री श्री नारा लोकेश, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रो. अभय करंदीकर, आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामाकोटी, डॉ. अमित सिंघी (आईबीएम रिसर्च इंडिया), डॉ. हैरिक विन (टीसीएस), श्री एम.वी. सतीश (एल एंड टी) सहित वरिष्ठ उद्योग जगत के नेता, वरिष्ठ राज्य अधिकारी, संकाय सदस्य और छात्र उपस्थित थे।

पायलट का वशीकरण करवाया, पीए साथ क्यों नहीं गया? अजित पवार की प्लेन क्रैश पर एनसीपी ने उठाए गंभीर सवाल, मचा बवाल

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन क्रैश में निधन के 10 दिन बाद एक बार फि कुछ नेताओं ने ऐसे सवाल किए है, जिसके बाद साजिश की आशंका खड़ी कर दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के कुछ नेताओं ने इस कथित घटना को सामान्य दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए गंभीर संदेह जताया है।

सांसद बजरंग सोनवणे ने यह सवाल उठाया कि अगर विमान हादसा था तो उसकी परिस्थितियां असामान्य क्यों बताई जा रही हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह आरोप नहीं बल्कि संदेह है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

NCP सांसद का दावा- अजित दादा के प्लेन में बम था जो फट गया

गौरतलब है कि अजित पवार को मुंबई से बारामती ले जा रहा विमान 28 जनवरी को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार सभी लोग मारे गए। इस घटना के बाद कई 'सिद्धांत' सामने आने लगे हैं। एनसीपी (शरद पवार समूह) के सांसद बजरंग सोनवणे ने तो यहां तक आशंका जताई कि विमान में बम था और वह हवा में ही फट गया।

एनसीपी विधायक ने कहा- 'पायलट का वशीकरण करवाया गया होगा'

रविवार को मीडिया से बात करते हुए एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने पायलट को लेकर चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने पायलट सुमित कपूर के 'वशीकरण' की संभावना जताई गई। मिटकरी ने इसे 'वशीकरण आतंकवादी' हादसा बताते हुए इसमें आत्मघाती हमलावर की भूमिका पर संदेह व्यक्त किया। राजीव गांधी और अजमल कसाब के मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कई आतंकी हमलों में ऐसे ही 'वशीकरण' का इस्तेमाल होता है।

प्रतिबंधित प्लेन का 'अजित दादा' की यात्रा के लिए क्यों भेजा गया?

मिटकरी ने विमान संचालन से जुड़ी कंपनी और पायलट की भूमिका पर सवाल खड़े किए। अमोल मिटकरी ने विमानन कंपनी वीएसआर पर तीखे आरोप लगाए। जिस प्लेन पर पहले से ही प्रतिबंध था, फिर भी 28 जनवरी को 'अजित दादा' की यात्रा के लिए उसी प्लेन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या 50 करोड़ रुपये के बीमा के लालच में बीमा कंपनी ने पायलट को ऐसा करने के लिए उकसाया होगा।

आरएसएस के प्रोग्राम में पहुंची अनन्या बिड़ला संभालती है 10 लाख करोड़ का बिजनेस

आदित्य बिड़ला ग्रुप की डायरेक्टर अनन्या बिड़ला इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, दरअसल उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुंबई व्याख्यानमाला कार्यक्रम की तारीफ की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 'यह सब

राष्ट्र निर्माण और एक भारतीय के तौर पर भारत को आगे ले जाने के बारे में है, मैं हर चीज के लिए उत्सुक हूं, बहुत अच्छा लगा यहां आकर।'

मालूम हो कि देश के शीर्ष रईसों में शुमार कुमार मंगलम बिड़ला की बेटी अनन्या बिड़ला अक्सर अपने बयानों या लुक के कारण सुर्खियों में रहती हैं। मात्र 31 साल की उम्र में अनन्या एक सफल एंटरप्रेन्योर, प्लैटिनम-सेलिंग पॉप स्टार और फिलांथ्रोपिस्ट हैं, खास बात ये है कि उन्होंने अभी तक जिस भी फील्ड में काम किया है उसमें वो सफल रही हैं।

बलां की खूबसूरत अनन्या बिड़ला कुमार मंगलम बिड़ला और नीरजा बिड़ला की सबसे बड़ी बेटी।

खुशखबरी, बेंगलुरू में नम्मा मेट्रो का नहीं बढ़ेगा किराया, आखिर क्यों वापस लिया गया फैसला?

(जीएनएस)।

बेंगलुरू में नम्मा मेट्रो पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर सामने आई है। बेंगलुरू मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने अपनी एनुअल ऑटोमैटिक फेयर रिविजन स्कीम को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। याद रहे ये 9 फरवरी (सोमवार) से लागू होने वाली थी। इस स्कीम के तहत शहर में सभी लाइनों की नम्मा मेट्रो के किराए में 5 फीसदी की बढोत्तरी होने वाली थी।

लेकिन मेट्रो का किराया बढ़ाए जाने के फैसले पर जनता के तीव्र विरोध और राज्य के कांग्रेस नेतृत्व तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच तीखी राजनीतिक तकरार के बाद ये मेट्रो के टिकट का किराया बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया गया है।

क्या नहीं बढ़ेगा मेट्रो का किराया?

BMRCL ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पुष्टि की है कि अगले आदेश तक मौजूदा किराया ही लागू रहेगा। निगम निदेशक मंडल संशोधित मूल्य स्लैब की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई तय करेगा।कॉर्पोरेशन ने अपने बयान में कहा, "5 फरवरी 2026 की मीडिया विज्ञप्ति में 9 फरवरी 2026 से वार्षिक

किराया संशोधन की घोषणा की गई थी, उसे अब अगले आदेश तक स्थगित रखा गया है। संशोधित किराए पर निर्णय बोर्ड की समीक्षा के बाद ही घोषित किया जाएगा।"

क्यों मेट्रो का किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया वापस?

यह विवाद तब गरमाया जब बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से याचिका करके उन्होंने इस किराया वृद्धि को रुकवाया है। सूर्या ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के प्रशासन पर "कमजोर वित्तीय स्थिति" की भरपाई के लिए किराया बढ़ाने का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने कांग्रेस की "जनता-लुभावन गारंटी योजनाओं" का परिणाम बताया।

सांसद ने किराया निर्धारण समिति (FFC) की रिपोर्ट में "mathematical errors" का भी जिक्र किया। उन्होंने तर्क दिया कि बेंगलुरु में पहले से ही भारत का सबसे महंगा मेट्रो सिस्टम है, और किसी भी अतिरिक्त वृद्धि से मध्यम वर्ग के लिए सार्वजनिक परिवहन बहुत महंगा और दुर्गम हो जाएगा।

जवाब में, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भाजपा के आरोपों को "जनता को गुमराह करने का जानबूझकर किया गया प्रयास" बताते हुए जिम्मेदारी से इनकार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 के तहत किराए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र समिति तय करती है, राज्य का इसमें कोई कानूनी अधिकार नहीं।

BMRCL ने क्या कहा?

डी.के. शिवकुमार ने जानकारी दी कि BMRCL बोर्ड ने उनसे इस संशोधन पर कोई परामर्श नहीं किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि समिति के अध्यक्ष एक केंद्रीय सरकारी सचिव हैं, जिससे विवाद का केंद्र प्रभावी रूप से केंद्र सरकार की ओर चला जाता है।

इस राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच, कल होने वाली BMRCL बोर्ड की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भाजपा का आग्रह है कि राज्य लागतों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक नई किराया निर्धारण समिति का औपचारिक रूप से अनुरोध करे। वहीं, कांग्रेस नेतृत्व का मत है कि मूल्य वृद्धि का प्राथमिक चालक वास्तव में केंद्रीय ढांचा ही है।

बेंगलुरु के लाखों दैनिक यात्रियों को फिलहाल अस्थायी राहत मिली है, हालाँकि "नम्मा मेट्रो" की दीर्घकालिक वहनीयता शहर के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है।

'सब्सिडी अमेरिका की, जोखिम भारत का' – भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर जीतू पटवारी का तीखा हमला

(जीएनएस)।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है।

उन्होंने इस समझौते को सीधे तौर पर किसान विरोधी बताते हुए कहा कि यह ऐसा करार है जिसमें सब्सिडी अमेरिका की है और जोखिम भारतीय किसानों पर डाला जा रहा है। जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री" करार देते हुए आरोप लगाया कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं और देश के किसानों के हितों से समझौता किया गया है।

जीतू पटवारी ने कहा कि यह केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि कई छिपे हुए समझौतों का पैकेज है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह डील अमेरिका में अडानी समूह से जुड़े मामलों को दबाने का प्रयास है, रूस से तेल नहीं खरीदने के अमेरिकी दबाव का हिस्सा है और उन मुद्दों से ध्यान हटाने का जरिया भी है, जिनमें प्रधानमंत्री का नाम एप्सटीन फाइल्स में सामने आया है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय दबाव में आकर देश के अन्नदाता की कीमत पर कोई भी सौदा स्वीकार्य नहीं हो सकता।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आयोजित बैठक और दिए गए बयानों के जरिए किसानों को आश्वस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक सरकार ने उत्पाद-वार टैरिफ संरचना, नॉन-टैरिफ बैरियर की शर्तें और इस समझौते की आधिकारिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों को मंच से दिए गए भाषण नहीं, बल्कि लिखित और ठोस गारंटी चाहिए, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रह सके।

जीतू पटवारी ने भारत और अमेरिका की कृषि संरचना में भारी

असमानता की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि अमेरिका में औसत कृषि जोत 440 से 450 एकड़ के आसपास है, जबकि भारत में यह मात्र 2 से 2.5 एकड़ है। अमेरिका में केवल 1 से 2 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है, जबकि भारत में बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। ऐसी असमान परिस्थितियों में यदि भारतीय किसानों को सब्सिडी-समर्थित अमेरिकी किसानों से खुली प्रतिस्पर्धा में उतारा जाएगा, तो इसका परिणाम भारतीय कृषि के लिए विनाशकारी होगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अमेरिका में "फार्म बिल" और अन्य योजनाओं के तहत किसानों को व्यापक सब्सिडी और वित्तीय सुरक्षा दी जाती है। भारत में जहां औसतन एक किसान को लगभग 14 हजार रुपये प्रतिवर्ष की प्रत्यक्ष सहायता मिलती है, वहीं अमेरिकी किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं अधिक आर्थिक समर्थन मिलता है। उन्होंने दिसंबर 2025 में अमेरिकी प्रशासन द्वारा फसल क्षति के लिए अरबों डॉलर की सहायता स्वीकृत किए जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां संकट के समय भी किसान पूरी तरह सुरक्षित रहता है, जबकि भारत का किसान हर झटके में सबसे पहले टूटता है।

जीतू पटवारी ने चेतावनी दी कि यदि नॉन-टैरिफ बैरियर कम किए जाते हैं या बाजार को चरणबद्ध तरीके से खोला जाता है, तो सब्सिडी-समर्थित सस्ता अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में प्रवेश करेगा। उन्होंने सवाल किया कि दो एकड़ जमीन वाला भारतीय किसान 450 एकड़ वाले सब्सिडी-संरक्षित अमेरिकी किसान से कैसे मुकाबला करेगा। यह असमान प्रतिस्पर्धा सीधे तौर पर भारतीय किसानों की आय और अस्तित्व पर हमला है।

उन्होंने सरकार की नीतियों में विरोधाभास की ओर इशारा करते हुए कहा कि सरकार यह दावा कर रही है कि मक्का का आयात नहीं होगा, लेकिन पोल्ट्री फीड या एनिमल फीड के नाम पर मक्का आधारित प्रोसेस्ड उत्पाद यदि आयात होते हैं, तो इसका सीधा असर देश के मक्का किसानों पर पड़ेगा। इसी तरह यदि सोयाबीन का आयात नहीं होगा, लेकिन सोयाबीन तेल आयात किया जाएगा, तो मध्यप्रदेश के लाखों सोयाबीन उत्पादक किसानों की आय दबाव में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि यह नीति किसानों के हितों के विपरीत है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में कृषि संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उस समय कृषि उत्पादों पर औसतन 30 से 60 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाया गया था और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में यह शुल्क 60 से 100 प्रतिशत तक रखा गया, ताकि विदेशी डंपिंग से भारतीय किसानों की रक्षा की जा सके। उन्होंने सवाल किया कि यदि आज 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत तक टैरिफ कम किया जा रहा है, तो सरकार यह स्पष्ट करे कि भारी असमानता के बावजूद भारतीय किसान वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कैसे टिक पाएगा।

जीतू पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री से सीधे सवाल करते हुए कहा कि क्या वे लिखित रूप से यह गारंटी देंगे कि सोयाबीन तेल आयात से किसानों को मिलने वाला मूल्य प्रभावित नहीं होगा, पोल्ट्री फीड आयात से मक्का किसानों को नुकसान नहीं पहुंचेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। उन्होंने मांग की कि उत्पाद-वार टैरिफ कटौती की विस्तृत सूची, नॉन-टैरिफ प्रावधानों का पूरा विवरण और इस ट्रेड डील की आधिकारिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तुरंत सार्वजनिक की जाए।

अंत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस व्यापार विस्तार के खिलाफ नहीं है, लेकिन अन्नदाता की कीमत पर कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जिस दिन भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम रूप से लागू होगी, उस दिन मध्यप्रदेश का किसान उसके विरोध में सड़कों पर उतरेगा और कांग्रेस किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरे प्रदेश में एकजुट होकर आंदोलन और जाम करेगी।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील ऐतिहासिक है और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां और गति देने वाली है- श्री शिवराज सिंह चौहान

भारत की नीति कमिटमेंट की है, कॉम्प्रोमाइज की नहीं

ट्रेड डील डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का प्रतीक

अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों को शून्य शुल्क पर मिलेगा बाजार

भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी उत्पाद ट्रेड डील में शामिल नहीं

ट्रेड डील किसानों, महिलाओं और युवाओं के सपनों को देगा नई उड़ान

आत्मनिर्भर-विकसित भारत के निर्माण में ऐसे सभी समझौते मील के पत्थर

(जीएनएस)।

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित निवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हुई हालिया ट्रेड डील को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति और नई ऊंचाइयां देने वाला साबित होगा। ट्रेड डील केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। यह डील भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ उसे नई दिशा प्रदान करेगी। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह समझौता पूरी दुनिया के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है। यह डील दुनिया को संदेश देती है कि भारत की नीति कमिटमेंट की है, कॉम्प्रोमाइज की नहीं। हम आत्मविश्वास के साथ देश के हित में निर्णय लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर संतुलित और सकारात्मक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सौदेबाजी की राजनीति नहीं करते, बल्कि संतुलित रणनीति अपनाकर सकारात्मक संवाद में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि आज भारत वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के रूप में उभर रहा है।

डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी

केन्द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, यह ट्रेड डील डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का एक उत्तम उदाहरण है। डिप्लोमेसी का अर्थ है राष्ट्र प्रथम, और इस समझौते में भारत के राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखे गए हैं। डेवलपमेंट यानी विकसित भारत की दिशा में बढ़ते कदम यह डील उसके लिए भी एक मजबूत आधार प्रदान करती है। डिग्निटी का मतलब है किसान की गरिमा, और मुझे गर्व है कि इस समझौते में किसान की गरिमा का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि और किसानों को लेकर

देश के मन में जो भी चिंताएं थीं, उनका इस ट्रेड डील में समाधान किया गया है। यह समझौता हमारे किसानों को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह डील केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि नए अवसरों का द्वार भी खोलती है। यह ट्रेड डील हमारे कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में नए अवसर प्रदान करेगी और किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। यही आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मजबूत नींव है।

अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर शून्य शुल्क

केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारतीय किसानों के कई कृषि उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात किया जाएगा। लेकिन अमेरिकी किसानों के कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में यह छूट नहीं मिली है। भारत के कृषि और डेयरी के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कृषि क्षेत्र के कई उत्पादों पर टैरिफ में बड़ी कटौती की है। कई कृषि उत्पादों पर जो टैरिफ पहले 50 प्रतिशत तक था, उसे अमेरिका ने घटाकर शून्य कर दिया है। इसमें मसाले, चाय, कॉफी, नारियल, नारियल तेल, सुपारी, काजू, वनस्पति वैक्स, एवोकाडो, केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, अनानास, मशरूम और कुछ अनाज भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि, वर्ष 2024-25 में भारत का कृषि निर्यात 4.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। मसाला निर्यात में 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब इस ट्रेड डील के बाद हमारे मसालों को अमेरिका में भी नया और बड़ा बाजार मिलेगा। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत पहले से ही मसालों के वैश्विक बाजार में मजबूत स्थिति रखता है। दुनिया भर के करीब 200 स्थानों पर भारत मसाले और मसालों के उत्पाद निर्यात करता है। इस समझौते से मसालों और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हुआ है। अगर विदेशी कृषि उत्पाद भारतीय कृषि बाजार में आते हैं, तो उन्हें टैरिफ देना होगा। हमारे किसानों को पूरी छूट और पूरा संरक्षण प्राप्त है। यही इस ट्रेड डील की सबसे बड़ी ताकत है।

सभी संवेदनशील वस्तुएं समझौते से बाहर

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील में कृषि और कृषि उत्पादों के मामले में भारतीय किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है और ऐसा कोई भी उत्पाद समझौते में शामिल नहीं है, जिससे किसानों को नुकसान हो। सभी संवेदनशील वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल और तंबाकू जैसे उत्पादों पर किसी भी तरह की टैरिफ छूट नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चिंता देश के प्रमुख अनाजों को लेकर थी। सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी कि हमारे प्रमुख अनाज सुरक्षित रहने चाहिए और मैं गर्व से कह सकता हूं कि वो सभी पूरी तरह सुरक्षित रखे गए हैं। प्रमुख अनाज, प्रमुख फल और डेयरी उत्पादों के लिए अमेरिका के लिए कोई द्वार नहीं खोला गया है। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि कई अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। छिलका रहित अनाज, आटा, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम, दलहनी उत्पाद, फ्रोजन सब्जियां, संतरे, अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी और मिक्स्ड डिब्बाबंद सब्जियां भारत नहीं आएंगी। डेयरी उत्पादों को लेकर भी उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादों में लिक्विड मिल्क, पाउडर, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर और चीज, इनमें से किसी को भी भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। कृषि और डेयरी के अलावा भारत, अमेरिका से काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, केसिया, सरसों, राई, भूसी और अन्य पाउडर मसाले नहीं मंगवाएगा। मतलब साफ है हमारे मसाले और हमारे किसान पूरी तरह सुरक्षित हैं।

किसान, महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि इस समझौते से भारतीय किसान, महिलाएं और खासकर युवा वर्ग को आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। हमारे कई सेक्टर जैसे टेक्सटाइल में अब प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में हमारा टैरिफ काफी कम होकर करीब 18 प्रतिशत रह गया है। इससे टेक्सटाइल निर्यात को नई गति और नई दिशा मिलेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल निर्यात का सीधा लाभ किसानों को भी मिलेगा। टेक्सटाइल का मतलब है किसानों को फायदा, खासकर कपास उत्पादक किसानों को। इसके साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट, इंजीनियरिंग गुड्स और एमएसएमई सेक्टर के लिए भी ढेर सारे नए व्यापारिक अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों का जीवन भी इस समझौते से समृद्ध होगा, क्योंकि कई उत्पादों के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह डील उनके परिश्रम और हुनर को वैश्विक पहचान दिलाएगी। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब तक नौ एफटीए हो चुके हैं। अमेरिका के अलावा यूएई के 27 देशों, ओमान, न्यूजीलैंड और यूके के साथ एफटीए किया जा चुका है और अन्य देशों से बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि इन सभी समझौतों का व्यापक लाभ देश को मिलेगा। इन डील्स का फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, निर्यातकों और निमार्ताओं को होने वाला है। इसी के माध्यम से हम 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में यह समझौता और ऐसे सभी समझौते मील के पत्थर साबित होंगे। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं।

बेलगावी हवाई अड्डे के पास मेसर्स रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के प्रशिक्षण विमान की आपातकालीन लैंडिंग

विमान का प्रकार: सेसना 172, पंजीकरण संख्या: वीटी-ईयूसी

(जीएनएस)।

आज, रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी के सेसना 172 विमान (वीटी-ईयूसी) को कलबुर्गी से बेलगावी रूट पर उड़ान भरते समय, ईंधन की कमी के कारण विजयपुरा के पास एक खुले मैदान में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। आपातकालीन लैंडिंग का स्थान बेलगावी हवाई अड्डे से 50 से 70 किलोमीटर दूर है। विमान में एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और एक प्रशिक्षु पायलट सवार थे। दोनों यात्री सुरक्षित हैं। टक्कर के कारण

विमान क्षतिग्रस्त हो गया है।

1. संगठन संबंधी जानकारी:

मेसर्स रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी एक डीजीसीए द्वारा अनुमोदित फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (एफटीओ) है, अनुमोदन संख्या 01/2020।

प्रारंभिक एफटीओ अनुमोदन 23/07/2020 को जारी किया गया था।

एफटीओ का अंतिम नवीनीकरण 23/07/2025 को हुआ था और यह 22/07/2030 तक वैध है।

बेड़े में विमानों की संख्या: 48 विमान

2. विमान का विवरण दिनांक 08/02/2026 के अनुसार:

निर्माण का वर्ष: 1975

सी ऑफ आर जारी करने की तिथि: 23/05/2023 (रेड बर्ड एफटीओ के साथ)।

प्रमाणन प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि: 20/09/2023

एआरसी जारी करने की तिथि: 01/08/2025, वैधता अवधि: 03/08/2026

समाचार प्रकाशित होने के बाद से समय (टीएसएन): 17512:40

3. इंजन विवरण

इंजन का प्रकार: लाइकमिंग ड320-ई2डी

इंजन घंटे: 802:10 घंटे

4. क्रू जानकारी

पीआईसी (फ्लाइट इंस्ट्रक्टर): सीपीएल धारक

अंतिम चिकित्सा जांच की तिथि: 18.03.2025 (19.03.2026 तक वैध)

उड़ान का समय: 734 घंटे

पिछली सूचना संचार/दक्षता जांच तिथि: 25.07.2025

आगे की जांच डीजीसीए/एएआईबी द्वारा की जाएगी।

दिल्ली में अब 50 हजार हाईटेक सीसीटीवी से बदलेगी महिलाओं की सुरक्षा की तस्वीर

(जीएनएस)।

राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार एक बार फिर बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। सरकार ने शहर भर में करीब 50,000 नए हाईटेक उउळश कैमरे लगाने का फैसला किया है।

यह कदम उन इलाकों पर फोकस करेगा, जहां अंधेरा रहता है या फिर सुरक्षा को लेकर पहले शिकायतें सामने आती रही हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 646.6 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

यह योजना क्यों है खास?

यह प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार की उस बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत राजधानी में 24 घंटे निगरानी वाली मजबूत सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 'Women Safety in Delhi' योजना के तहत शुरूआती तौर पर 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि लगातार निगरानी से अपराध पर अंकुश लगेगा और महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा।

कहां-कहां लगाए जाएंगे कैमरे?

पीडब्ल्यूडी के शुरूआती आकलन के अनुसार, दिल्ली के उन सभी इलाकों को चुना गया है जहां रोशनी कम रहती है या फिर महिलाओं की आवाजाही ज्यादा होती है। इन जगहों पर करीब 49,900 चार-मेगापिक्सल क्ढ बुलेट CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे रळदउ मानकों के अनुसार होंगे और हर कैमरे में 512GB का लोकल स्टोरेज दिया जाएगा। इन स्थानों का चयन महिला एवं बाल विकास विभाग और दिल्ली पुलिस के इनपुट के आधार पर किया गया है।

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब फाइलों में नहीं अटकेगा विकास! MCD आयुक्त को 50 करोड़ तक मंजूरी का अधिकार

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब फाइलों में नहीं अटकेगा विकास! MCD आयुक्त को 50 करोड़ तक मंजूरी का अधिकार

रात में गाड़ियों पर कैसे रहेगी नजर?

रात के समय निगरानी और वाहनों की पहचान को और मजबूत करने के लिए 100 हाई-रेजोल्यूशन ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन यानी अठढफ कैमरे भी लगाए जाएंगे। इनमें इन्फ्रारेड विजन होगा, जो 100 मीटर की दूरी से भी नंबर प्लेट कैप्चर कर सकेगा। अधिकारियों के मुताबिक, इससे रियल-टाइम मॉनिटरिंग के साथ-साथ किसी भी वारदात के बाद जांच में बड़ी मदद मिलेगी।

हर पोल पर कितने कैमरे लगेंगे?

इस योजना के तहत शहर में करीब 17,000 आठ-मीटर ऊंचे पोल लगाए जाएंगे। हर पोल पर दो से तीन बुलेट कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं ANPR कैमरों के लिए 100 अलग पोल लगाए जाएंगे, जिन पर अतिरिक्त सुरक्षा कवच भी होगा। इससे कैमरों की सुरक्षा और टिकाऊपन दोनों सुनिश्चित किए जाएंगे।

बिजली और बैकअप का क्या इंतजाम है?

जहां बिजली की लाइन उपलब्ध नहीं है, वहां करीब 5,000 सोलर पैनल सिस्टम लगाए जाएंगे। इनमें लिथियम-आयन बैटरी होगी, जो कम से कम 14 घंटे का बैकअप देगी। इसके अलावा 12,100 वढर यूनिट्स भी लगेंगी, जो करीब 30 मिनट का बैकअप देंगी। कैमरों से आने वाले डेटा के लिए फायरवॉल से सुरक्षित स्टोरेज सिस्टम और एक सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर बनाने का भी प्रस्ताव है।

कब तक पूरा होगा प्रोजेक्ट?

इस प्रोजेक्ट का खर्च कई सालों में किया जाएगा। 2025-26 में 50 करोड़ रुपये, 2026-27 में 300 करोड़ रुपये और बाकी राशि 2031-32 तक किस्तों में खर्च की जाएगी। सरकार का दावा है कि यह कदम दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को एक नई मजबूती देगा और राजधानी को और सुरक्षित बनाएगा।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

दिलचस्प मोड़ पर द. एशिया की राजनीति

भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा के बाद दक्षिण एशिया की राजनीति में दिलचस्प मोड़ आने की संभावना बढ़ गईं है क्योंकि ट्रंप प्राशासन के दौरान अमेरिकी व्यापार प्रातिनिधि (यूएसटीआर) द्वारा जारी किया गया भारत का मानचित्र पाक अधिवृत कश्मीर (पीओके) और अक्साईं चिन को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। भले ही यह मानचित्र चुपचाप जारी किया गया हो किन्तु सोशल मीडिया और कूटनीतिक क्षेत्र में इस मानचित्र की वजह से अत्याधिक हलचल मची हुईं है।

इससे एक बात तो साफ हो गईं है कि अमेरिका अब महसूस करने लगा है कि यदि वह भारत के साथ संबंध अच्छे कर ले जाए तो निश्चित रूप से एशिया में वह बुलंदियों को छू सकता है। इसलिए इस मानचित्र के जारी होने को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान को तो वह आईएमएफ, विश्व बैंक और खाड़ी के देशों से उधार दिलवाकर अपने वश में रख सकता है किन्तु भारत को अपने साथ खड़ा रखने के लिए उसके साथ ठोस रणनीतिक संबंध बनाना जरूरी है। भारत कोईं जवाब दे या न दे, अमेरिका ने भारत को स्पष्ट एवं दो टूक जवाब दे दिया है कि नईं दिल्ली के दोनों पड़ोसियों द्वारा थोपी गईं रणनीतिक समस्याओं को लेकर अमेरिका भारत के साथ ही रहेगा। पूर्व में पीओके के मामले में अमेरिका ने पहले तो अपनी भूमिका तलाशने की कोशिश की थी। लेकिन भारत ने 1971 के बाद स्पष्ट रूप से उसे समझा दिया कि कश्मीर मुद्दा द्विपक्षीय है इसलिए अमेरिका की कोईं जरूरत है ही नहीं। 1990 के दशक में जब बिल क्लिटन का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तब उन्होंने भारत के महत्व को समझा और भारत विरोधी अपने स्टेट डिपार्टमेंट के महत्वपूर्ण नीति निर्धारकों को इधर से उधर करके भारत के प्राति सकारात्मक नजरिया रखने वालों को दक्षिण एशिया डेस्क पर तैनात किया। राबिन रापेल के स्थान पर इण्डरफर्थ की नियुक्ति के बाद अमेरिका ने अपनी कश्मीर नीति में व्यापक बदलाव किया। उसी वक्त से भारत के साथ अमेरिका के कईं बार खट्टे-मीठे संबंध बने बिगड़े किन्तु अमेरिका कश्मीर पर कोईं बयान देने से बचता रहा। वह ज्यादा से ज्यादा यही कहता रहा कि यदि भारत और पाकिस्तान दोनों चाहें तो वाशिगटन डीसी समझौता कराने की पहल कर सकता है किन्तु भारत के कड़े रुख को देखते हुए अमेरिका सार्वजनिक रूप से फटे में टांग अड़ाने से बचता रहा है। जहां तक अक्साईं चिन का सवाल है तो अमेरिका हमेशा चीन के खिलाफ रहा। 1962 में तो चीन ने एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा ही तब कर दी थी जब अमेरिकी वायुसेना चुसूल हवाईं अड्डे पर स्थिति का आंकलन करने पंडित जवाहर लाल नेहरू के आग्राह पर आ गईं। यदि चीन उस वक्त युद्ध विराम की घोषणा न करता तो अमेरिका ब्रिटिश वायुसेना के साथ चीन के खिलाफ कार्रवाईं करने का पैसला कर ही चुका था।

सवाल यह है कि इस वक्त अमेरिका अपने समर्थक पाकिस्तान की भावनाओं को ठुकराकर लगातार पैसले क्यों ले रहा है? पहले वीजा की सूची से पाकिस्तान को बाहर करना और फिर पाकिस्तान के उत्पादों पर लगाए गए 19 प्रातिशत टैरिफ से एक प्रातिशत कम टैरिफ भारतीय उत्पादों पर लगाना और अब खुलकर भारत के कश्मीर विवाद में कूदना और समूचे जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा बताना, इस बात का द्योतक है कि अब अमेरिका किसी भी हालत में भारत को इस बात का एहसास दिलाना चाहता है कि अमेरिका भारत का सच्चा रणनीतिक सहयोगी है इसलिए भारत को चाहिए कि वह भी खुलकर वाशिगटन डीसी के हितों के प्राति संवेदनशीलता दिखाए।

सच तो यह है कि इस वक्त ट्रंप की भारत विरोधी नीतियों के कारण प्रावासी भारतीय अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से अत्याधिक नाराज हैं।

जहां-जहां चुनाव हुए हैं, ट्रंप की कार्यशैली की वजह से हर चुनाव में डेमोक्रेट हारे हैं। अब टेक्सास में सीनेट का उपचुनाव है और रिपब्लिकन पार्टी की सीनेट में मात्र 4 सीट डेमोक्रेट से ज्यादा होने के कारण यह चुनाव ट्रंप प्राशासन के स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।

भारत के प्रधानमंत्री की मलेशिया की आधिकारिक यात्रा के अवसर पर भारत-मलेशिया का संयुक्त वक्तव्य

(जीएनएस)।

मलेशिया के प्रधानमंत्री महामहिम दातो सेरी अनवर इब्राहिम के आमंत्रण पर भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 से 8 फरवरी 2026 तक मलेशिया की आधिकारिक यात्रा की। यह यात्रा दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों पर आधारित गहरी मित्रता और अटूट जन-संबंधों को दशार्ती है। इसने भारत-मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने एवं विस्तार करने के लिए दोनों नेताओं की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

1957 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से, मलेशिया और भारत ने आपसी सम्मान और साझा मूल्यों पर आधारित साझेदारी की है। इस साझेदारी को अगस्त 2024 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) का दर्जा दिया गया।

यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी का पुत्राजाया स्थित पदार्ना पुत्रा परिसर में औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इसके बाद, दोनों नेताओं ने 8 फरवरी 2026 को आधिकारिक द्विपक्षीय बैठकें की और सीएसपी की पुष्टि की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में व्यापक और सार्थक चर्चा की जिसमें राजनीतिक जुड़ाव, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, समुद्री सहयोग, व्यापार एवं निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, युवा आदान-प्रदान एवं जन-जन संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलू शामिल थे। इसके अतिरिक्त, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक आधिकारिक भोज का आयोजन भी किया। उन्होंने संस्थागत सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से कई द्विपक्षीय दस्तावेजों के आदान-प्रदान को भी देखा।

दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध, सदियों पुराने संपर्क, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्य, तथा मलेशिया में जीवंत भारतीय समुदाय की उपस्थिति, द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक अद्वितीय, मजबूत और स्थायी आधार का कार्य करते हैं और इसके बहुआयामी स्वरूप को समृद्ध करते हैं।

राजनीतिक सहयोग

दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि उच्च स्तरीय दौरों सहित नियमित संवाद एवं आदान-प्रदान ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी समझ और समन्वय को मजबूत किया है। उन्होंने पारस्परिक हित के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर निरंतर जुड़ाव के महत्व को दोहराया।

इस संदर्भ में, विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) और संयुक्त आयोग की बैठकें (जेसीएम) मलेशिया-भारत संबंधों को आधार प्रदान करने वाले प्रमुख मंच बने हुए हैं।

संसदीय लोकतंत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता से प्रेरित दोनों नेताओं ने संसदीय सहयोग और आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया और कहा कि इस प्रकार के जुड़ाव ने संस्थागत संबंधों को मजबूत किया है और आपसी समझ को गहरा किया है। उन्होंने हाल ही में 13-16 जनवरी 2026 तक आयोजित की गई राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन (सीएसपीओसी) में मलेशियाई प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, तन श्री दातो डॉ. जोहरी अब्दुल की भारत यात्रा पर संतोष व्यक्त किया। इसके अलावा, उन्होंने सितंबर 2025 में आसियान अंतर-संसदीय सभा (एआईपीए) की 46वीं महासभा के लिए भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की मलेशिया यात्रा और 31 मई से 3 जून 2025 तक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की मलेशिया यात्रा पर भी संतोष व्यक्त किया।

व्यापार और निवेश में सहयोग

मलेशिया भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक भागीदार मानते हुए, द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की सराहना करता है। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह साझेदारी पारस्परिक महत्व और रणनीतिक तालमेल पर आधारित है। दोनों नेताओं ने संतुलित सहयोग की भावना से प्रेरित होकर, व्यापार सुगमता बढ़ाने और सेमीकंडक्टर, डिजिटल अर्थव्यवस्था और औद्योगिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की।

नेताओं ने मलेशिया-भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (एमआईसीईसीए) और आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने एआईटीआईजीए की चल रही समीक्षा का स्वागत किया ताकि इसे पारस्परिक रूप से लाभकारी, व्यापार सुगम और वर्तमान वैश्विक व्यापार व्यवस्थाओं के अनुरूप बनाया जा सके। दोनों नेताओं ने आर्थिक संबंधों को गहरा करने की एमआईसीईसीए की क्षमता की सराहना की और इसके अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित किया।

भारत-मलेशिया संबंधों की नई सुबह संस्कृति, व्यापार और रणनीति की साझा यात्रा

प्रधानमंत्री मोदी का यह मलेशिया दौरा इस बात का संकेत है कि भारत और मलेशिया अपने ऐतिहासिक संबंधों को नईं ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। संस्कृति, व्यापार, सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग के जरिए यह साझेदारी आने वाले वर्षो में और गहरी हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आठ वर्षो बाद मलेशिया पहुँचना केवल एक राजनयिक दौरा नहीं, बल्कि भारत-मलेशिया संबंधों में विश्वास, आत्मीयता और भविष्य की साझेदारी को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण क्षण है। कुआलालंपुर हवाईं अड्डे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करना और उन्हें अपनी कार से कार्यक्रम स्थल तक ले जाना, दोनों देशों के रिश्तों की गर्मजोशी और आपसी सम्मान को दशार्ता है। यह दृश्य इस बात का संकेत है कि भारत और मलेशिया के संबंध अब औपचारिकताओं से आगे बढ़ व्यक्तिगत भरोसे और गहरी समझ के स्तर पर पहुँच चुके हैं।

भारत और मलेशिया के रिश्तों की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। सदियों पहले समुद्री मार्गो के जरिए भारतीय व्यापारी, विद्वान और सांस्कृतिक परंपराएँ मलाया प्रायद्वीप तक पहुँचीं। मसाले, नारियल, चाय और वस्त्रों के व्यापार के साथ-साथ भाषा, धर्म और संस्कृति का आदान-प्रदान भी हुआ। आज भी मलेशिया की संस्कृति में भारतीय प्रभाव साफ दिखाईं देता है, विशेषकर तमिल समुदाय के माध्यम से। प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि कुआलालंपुर और कोच्चि में स्वाद एक जैसा लगता है, केवल भोजन का वर्णन नहीं है, बल्कि उस साझा सांस्कृतिक विरासत की ओर संकेत है जो दोनों देशों को जोड़ती है।

राजनयिक स्तर पर भारत और मलेशिया के संबंध मलेशिया की स्वतंत्रता के तुरंत बाद स्थापित हो गए थे। समय के साथ इन रिश्तों ने मजबूती हासिल की और दोनों देशों ने आपसी विश्वास के आधार पर सहयोग के नए आयाम जोड़े।

वर्ष 2015 में इन संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया और बाद में इसे व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला गया। इसका अर्थ यह है कि भारत और मलेशिया केवल व्यापार या राजनीतिक संवाद तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रक्षा, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, शिक्षा और लोगों के आपसी संपर्क जैसे दीर्घकालिक और संवेदनशील क्षेत्रों में भी मिलकर काम कर रहे हैं।

मलेशिया में लगभग उनतीस लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो विश्व के सबसे बड़े भारतीय प्रवासी समुदायों में से एक हैं। यह समुदाय दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु की भूमिका निभाता है।

भारतीय मूल के नागरिक मलेशिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति, शिक्षा और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वहीं भारत के लिए यह समुदाय भावनात्मक ही नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यही कारण है कि हर भारतीय प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा में प्रवासी भारतीय समुदाय विशेष केंद्र में रहता है।

व्यापार भारत-मलेशिया संबंधों का एक मजबूत स्तंभ है।

मलेशिया भारत का दक्षिण-पूर्व एशिया में एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ा है, हालांकि भारत को कुछ वर्षो से व्यापार घाटे की चुनौती का सामना करना पड़ा है। भारत मलेशिया से मुख्य रूप से खाद्य तेल आयात करता है, विशेष रूप से पाम तेल, जो भारत की घरेलू आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। इसके अलावा भारत मलेशिया से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अर्धचालक से जुड़े पुर्ज़े, रसायन, पेट्रो रसायन उत्पाद, रबर और लकड़ी से बने सामान भी आयात करता है।

दूसरी ओर भारत मलेशिया को पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयाँ, वाहन, इस्पात, रसायन, वस्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाएं निर्यात करता है। भारतीय दवा उद्योग मलेशिया में अच्छी पहचान रखता है, क्योंकि भारत की सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ वहाँ के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इसी तरह भारतीय तकनीकी कंपनियां मलेशिया के डिजिटल विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार को अधिक संतुलित और टिकाऊ बनाने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की समीक्षा की जा रही है, ताकि भारतीय उद्योगों और मलेशियाईं भागीदारों दोनों को समान लाभ मिल सके।

मलेशिया से भारत को कच्चे माल और रणनीतिक आपरूति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिलता है।

अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में मलेशिया की वैश्विक भूमिका भारत के लिए खास मायने रखती है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया आपरूति श्रृंखला को विविध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं मलेशिया के लिए भारत एक विशाल बाजार, तेज़ी से बढ़ अर्थव्यवस्था और निवेश के असीम अवसरों वाला देश है।

भारत की जनसंख्या, डिजिटल चा और निर्माण क्षमता मलेशियाईं कंपनियों को आर्कषित करती है।

रणनीतिक और सुरक्षा के स्तर पर भी भारत और मलेशिया एकदूसरे के लिए बेहद अहम हैं।

मलक्का जलडमरूमध्य विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गो में से एक है, जहाँ से वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और अवैध गतिविधियों से निपटना दोनों देशों की साझा प्राथमिकता है।

भारत की हिंद-प्रशांत दृष्टि और मलेशिया की क्षेत्रीय भूमिका एकदूसरे के पूरक हैं। नौसैनिक सहयोग और रक्षा संवाद के माध्यम से दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दे रहे हैं। डिजिटल और वित्तीय तकनीक के क्षेत्र में सहयोग भारत-मलेशिया संबंधों को भविष्य की दिशा दे रहा है। भारत का डिजिटल भुगतान तंत्र अब विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है और मलेशिया में इसके विस्तार से न केवल

पीड़ा की धरती पर आशा का वृक्ष: बाबा आमटे

कुछ लोग जन्म लेकर नहीं,बल्कि अपने कर्मो से अमर बनते हैं। वे समय की सीमाओं को लांघकर समाज की आत्मा में स्थायी स्थान बना लेते हैं। बाबा आमटे ऐसे ही विरले व्यक्तित्व थे, जिनका संपूर्ण जीवन करुणा, साहस और सेवा का उज्ज्वल प्रतीक बन गया। 9फरवरी 2008 को भले ही उनकी देह नश्वरता में विलीन हो गईं हो,परंतु उनके विचार आज भी असंख्य जीवनों को दिशा और ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। वे केवल एक समाजसेवक नहीं, बल्कि मानवीय चेतना की सजीव अभिव्यक्ति थे, जिन्होंने पीड़ा को संबल और दुर्बलता को आत्मविश्वास में बदल दिया। उनके लिए सेवा कोईं औपचारिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आत्मा की तपस्या थी। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि स्थायी परिवर्तन बाहरी सहायता से नहीं,बल्कि अंतर्मन की जागृति से उत्पन्न होता है। 26 दिसंबर 1914को महाराष्ट्र के हिगणघाट, वर्धा में जन्मे मुरलीधर देवीदास आमटे का प्रारंभिक जीवन वैभव और सुविधा से सुसज्जित था।

संपन्न परिवार में पले-बढ़े बाबा आमटे ने बचपन से ही ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा और आधुनिक जीवनशैली का अनुभव किया। आकर्षक वस्त्र, तेज रफ्तार वाहन और सामाजिक सम्मान उनके दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा थे।

कितु इस भौतिक चमक-दमक के पीछे उनके मन में एक गहन बेचैनी निरंतर करवट लेती रहती थी। वे जीवन को केवल सुख-साधनों का साधन नहीं मानते थे, बल्कि उसे किसी महान उद्देश्य से जोड़ना चाहते थे। यही आंतरिक मंथन धीरे-धीरे उनके व्यक्तित्व को रूपांतरित करता गया और उन्हें आत्मकेंद्रित सोच से निकालकर सामाजिक दायित्व की ओर अग्रसर करता चला गया। शिक्षा और बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में बाबा आमटे ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त कीं। नागपुर से बी.ए. और एल.एल.बी. की उपाधि प्राप्त कर वे एक सक्षम और प्रतिष्ठित वकील बने। न्यायालयों में कार्य करते हुए उन्होंने देखा कि कानून की पहुंच अक्सर निर्बल और वंचित वर्ग तक नहीं हो पाती। निर्णय तो होते थे, परंतु पीड़ितों की पीड़ा अनसुनी रह जाती थी। इसी काल में एक उपेक्षित कुष्ठ रोगी को असहाय अवस्था में देखकर उनका अंतःकरण विचलित हो उठा। समाज द्वारा ठुकराए गए उस मानव की दुर्दशा ने उनकी आत्मा को भीतर तक झकझोर दिया। उसी क्षण उन्होंने दृढ़ निाय किया कि वे अपना संपूर्ण जीवन उन लोगों के उत्थान के लिए सर्मपित करेंगे, जिन्हें समाज ने उपेक्षा और तिरस्कार के अंधकार में छोड़ दिया है। जब संकल्प सच्चा हो और उद्देश्य पवित्र,तब वह इतिहास का

कौन हैं रूबल नागी? बला की खूबसूरत महिला ने जीता 'ग्लोबल टीचर प्राइज', रातोंरात बन गई करोड़पति

(जीएनएस)।

भारत की जानी-मानी कलाकार और सोशल वर्कर रूबल नागी ने शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन किया है। रूबल नागी को वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित 'ग्लोबल टीचर प्राइज' से दुबई में सम्मानित किया गया है।

इस अवार्ड के बाद रूबल नागी लगातार सुर्खियों में हैं। जानिए कौन है रूबल नागी और उन्होंने ऐसी क्या पहल की है कि जिसकी बदौलत उन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है? लोबल टीचर प्राइज पाकर रूबल नागी रातोंरात बनीं करोड़पति

दुबई में आयोजित World Government Summit के दौरान रूबल नागी की दो दशक लंबी सामाजिक यात्रा को दुनिया ने सराहा। GEMS Educationf Global Teacher Prize जिसे शिक्षा जगत का "नोबेल पुरस्कार" कहा जाता है, इसके तहत रूबल नागी को $1 मिलियन यानी 9 करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि मिली है।

139 देशों को पछाड़ कर रूबक नागी ने जीता खिताब

ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 के लिए 139 देशों से 5,000 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें से रूबल नागी का चयन किया गया। उन्हें यह पुरस्कार दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और वर्की फाउंडेशन के फांडडर सनी वर्की द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार वर्की फाउंडेशन द्वारा UNESCO के सहयोग से दिया जाता है। कौन हैं रूबल नागी?

रूबल नागी मुंबई की रहने वाली एक प्रसिद्ध कलाकार, म्यूरलिस्ट और सोशल वर्क हैं। इनका जन्म जम्मू-कश्मीर में हुआ और उन्होंने लंदन के SlÔde School of Fine Art से आर्ट सब्जेक्ट की पढ़ाई की। शुरूआत में वह अपनी मूर्तिकला और भित्ति चित्रों के लिए पहचानी गईं।

लेकिन बाद में रूबल ने कला को सामाजिक बदलाव का माध्यम बनाते हुए "क्लासरूम" की पारंपरिक अवधारणा को पूरी तरह से नया रूप दिया। इसी सोच के साथ उन्होंने Rouble Nagi Art FoundÔtion (RNAF) की स्थापना की।

कौन हैं विधु विनोद चोपड़ा के बेटे अग्नि चोपड़ा? पाकिस्तान में खेलने के लिए किया रजिस्ट्रेशन? सामने आया सच

(जीएनएस)।

सोशल मीडिया पर इस समय एक खबर ने क्रिकेट और बॉलीवुड गलियारों में हलचल मचा दी है। मशहूर फिल्म निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ('12th फेल' फेम) के बेटे अग्नि देव चोपड़ा का नाम पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 की ऑक्शन लिस्ट में देखे जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। लेकिन अब इस युवा क्रिकेटर ने खुद सामने आकर इस पूरे मामले की सच्चाई बताई है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की एक कथित ऑक्शन लिस्ट वायरल हुई। इस लिस्ट में अग्नि देव चोपड़ा का नाम 822वें नंबर पर दर्ज था। उन्हें वरअ (अमेरिका) के खिलाड़ी के रूप में दिखाया गया था और उनकी बेस प्राइस करीब 6 लाख पाकिस्तानी रुपये (PKR 600,000) बताई गई थी। जैसे ही यह खबर फैली, नेटिजन्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

अग्नि चोपड़ा ने दी सफाई

विवाद बढ़ता देख अग्नि देव चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे नाम से एक टूर्नामेंट (PSL) को लेकर गलत और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि मैंने PSL के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। मेरा पूरा ध्यान इस समय अमेरिका (USA) में अपने क्रिकेट करियर और भविष्य के लक्ष्यों पर है। कृपया ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें।

कौन हैं अग्नि देव चोपड़ा? (क्रिकेट करियर और रिकॉर्ड्स)

अग्नि देव चोपड़ा केवल एक स्टार किड नहीं हैं, बल्कि एक क्रिकेटर भी हैं। उनके बारे में कुछ खास बातें शायद कम लोग जानते हैं. अग्नि ने भारत में मिजोरम के लिए खेलते हुए अपने पहले 4 प्रथम श्रेणी (First-Class) मैचों में लगातार 5 शतक जड़कर इतिहास रचा था। उन्होंने 11 प्रथम श्रेणी मैचों में लगभग 95 की औसत से 1804 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक शामिल हैं।

USA कनेक्शन

अग्नि का जन्म अमेरिका के डेट्रायट में हुआ था, इसलिए उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट है। बीसीसीआई के नियमों के कारण उन्होंने भारतीय घरेलू क्रिकेट छोड़कर अब वरअ से खेलने का फैसला किया है। वे मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में MI New York टीम का हिस्सा हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध तनावपूर्ण हैं और कोई भी भारतीय खिलाड़ी PSL नहीं खेलता, इसलिए अग्नि का नाम लिस्ट में आना चौंकाने वाला था। हालांकि, अग्नि अमेरिकी नागरिक हैं, फिर भी उनकी भारतीय जड़ों के कारण इस खबर ने तूल पकड़ा।

नेपाल के सामने इंग्लैंड को आया पसीना, अंतिम गेंद तक चले मैच में इंग्लिश टीम ने 4 रनों से जीता मुकाबला

T20 World Cup 2026 में आज क्रिकेट प्रशंसकों को वह मुकाबला देखने को मिला, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। इंग्लैंड और नेपाल के बीच खेला गया यह मैच किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था, जहां जीत और हार का फैसला अंतिम गेंद तक लटका रहा। एक तरफ अनुभव से भरी विश्व विजेता इंग्लैंड की टीम थी, तो दूसरी तरफ अपने जज्बे से इतिहास रचने को बेताब नेपाल के जांबाज।

पूरे मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की सांसें थमी रहीं। नेपाल ने जिस तरह से दिग्गज इंग्लिश गेंदबाजों का सामना किया, उसने साबित कर दिया कि क्रिकेट में अब कोई भी टीम 'छोटी' नहीं रही। इस बेहद करीबी मुकाबले ने टूर्नामेंट में रोमांच का नया तड़का लगा दिया है।

इंग्लैंड की पारी, बेथेल और ब्रूक का धमाका

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरूआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट सस्ते में पवेलियन लौट गए, जिससे टीम दबाव में आ गई थी। लेकिन इसके बाद मध्यक्रम ने मोर्चा संभाला। युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 35 गेंदों में 55 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके शामिल थे।

कप्तान हैरी ब्रूक ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और 32 गेंदों पर 53 रनों की कप्तानी पारी खेली। अंत में विल जैक्स ने मोर्चा संभाला और महज 18 गेंदों में नाबाद 39 रन बनाकर इंग्लैंड के स्कोर को 20 ओवर में 7 विकेट पर 184 रन तक पहुंचाया।

नेपाल का पलटवार, रोहित पौडेल और दिपेंद्र की जुझारू पारी

185 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेपाल की टीम ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। सलामी बल्लेबाज कुशल भुर्तेल ने टीम को तेज शुरूआत दी।

जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में रखें, स्वस्थ चर्चा से कराएं प्रदेश का विकासः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में सर्वदलीय बैठक को किया संबोधित

(जीएनएस)।

लखनऊ। विधान मंडल का बजट सत्र 9 फरवरी (सोमवार) से प्रारंभ होगा। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री व नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने का अनुरोध करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में रखें और इस पर स्वस्थ

चर्चा कर प्रदेश में विकास को गति प्रदान करने के लिए सरकार का सहयोग करें। विधानसभा सत्र संचालन के संबंध में विधान भवन में आयोजित इस सर्वदलीय बैठक में नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। स्वस्थ चर्चा से प्रदेश का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान होता है। जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के हित से जुड़े हर मुद्दों पर सदन में सुचारु रूप से चर्चा करनी चाहिए। सदन के संचालन में किसी प्रकार की बाधाएं न आये इसका ध्यान सभी सदस्यों को रखना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सदन के सुचारु संचालन के लिए सभी सदस्यों का सहयोग मांगा। बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद, कांग्रेस की आराधना मिश्रा ह्यमोनाह्न, निषाद पार्टी के रमेश सिंह, लोकदल के राजपाल बालियान, अपना दल के रामनिवास वर्मा आदि मौजूद रहे।

कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में राहत बनी यूपी सरकार 'गंभीर बीमारी सहायता योजना' बिना आयुष्मान कार्ड भी मिलेगा इलाज

(जीएनएस)।

लखनऊ। कैंसर एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही इंसान सिहर उठता है। तेजी से फैलती इस बीमारी से लड़ना जहां मानसिक और शारीरिक रूप से कठिन होता है वहीं इलाज का भारी खर्च कई परिवारों की कमर तोड़ देता है। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर एक बार फिर यह सवाल सामने आया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग महंगे इलाज का बोझ कैसे उठाएं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की ह्यनिर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजनाह्न जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। यह योजना खास तौर पर पंजीकृत निर्माण कामगार श्रमिकों के लिए है। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आयुष्मान भारत कार्ड या आयुष्मान

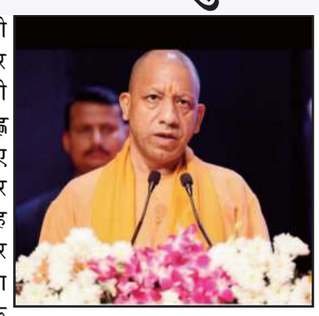

वय वंदना कार्ड होना अनिवार्य नहीं है। आयुष्मान योजना की तरह इसमें इलाज पर खर्च की कोई अधिकतम सीमा भी तय नहीं की गई है जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक चिंता काफी हद तक कम हो जाती है। इस योजना के अंतर्गत न केवल आयुष्मान भारत योजना में शामिल बीमारियों का इलाज कराया जा सकता है बल्कि इसके अलावा 13 अन्य गंभीर बीमारियों जिनमें कैंसर प्रमुख है कैंसर का भी उपचार संभव है। सरकार की यह पहल उन श्रमिक परिवारों के लिए संजीवनी साबित हो रही है जो सीमित आय के कारण गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करा पाते थे। यह योजना न सिर्फ इलाज सुनिश्चित करती है, बल्कि जीवन बचाने की एक मजबूत उम्मीद भी देती है।

पीलीभीत में सपा का आरोपः फर्जी वोट काटने की साजिश, भाजपा पर लगे धांधली के इल्जाम

(जीएनएस)।

पीलीभीत। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यूसुफ कादरी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी वोटरों के नाम काटने की साजिश रचने का इल्जाम ठोका है। रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कादरी ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने इस धांधली को नहीं रोका तो सपा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी।

कादरी ने बताया कि जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के इशारे पर 50 हजार से अधिक प्रिंटेड फॉर्म (प्रारूप संख्या 7) बांटे गए हैं। हर बूथ पर 50 से 100 मतदाताओं के खिलाफ फर्जी हस्ताक्षरों से आपत्तियां दर्ज कराई जा

रही हैं। भाजपा कार्यकर्ता बूथों पर जाकर फर्जी नामों से शिकायतें करा रहे हैं और बीएलओ पर दबाव बना रहे हैं।

उन्होंने मानपुर गांव का उदाहरण दिया, जहां 115 प्रिंटेड फॉर्म सामने आए। इनमें सतपाल नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर बताए गए, जिन्होंने एसडीएम कार्यालय में बयान दर्ज कराया कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और हस्ताक्षर फर्जी हैं। सतपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे तो शिकायत करना भी नहीं आता।" इसी तरह बाकरगंज, मुडालिया गौस, शाही नूरपुर और रफातनगर में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। सपा नेता ने सिटी मजिस्ट्रेट व एसडीएम सदर को अवगत कराया है। उन्होंने जिलाधिकारी से फर्जी हस्ताक्षर करने वालों, बीएलओ और शिकायतकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कादरी ने कहा कि 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी होने पर सपा हर वोट का मिलान करेगी। यदि निष्पक्ष जांच न हुई तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन होगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतपाल भी मौजूद थे, जिनके नाम पर 115 वोट काटने की कोशिश हुई।

पीलीभीत में गाय को लाठी-डंडों से पीटा,वीडियो वायरलः पुलिया से नीचे फेंका, हिंदू संगठनों का आक्रोश

माधोटांडा थाना क्षेत्र में बरुआ फजुलागंज के दो ग्रामीणों ने की क्रूरता, पुलिस ने जांच शुरू की

(जीएनएस)।

पीलीभीत,जिले के माधोटांडा थाना क्षेत्र के बरुआ फजुलागंज में दो ग्रामीणों ने एक गाय को लाठी-डंडों से जमकर पीटा और फिर उसे पुलिया से नीचे गहरे पानी में फेंक दिया। इस अमानवीय घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से क्षेत्र में तनाव फैल गया है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो व्यक्ति लाठियों से गाय पर लगातार हमला कर रहे हैं। गाय दर्द से

कराह रही है, लेकिन आरोपियों ने उस पर कोई रहम नहीं दिखाया। पिटाई के बाद उन्होंने गाय को घसीटते हुए पुलिया से नीचे धकेल दिया। वीडियो सार्वजनिक होते ही लोगों में रोष फैल गया और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल (पूरनपुर इकाई) के कार्यकर्ता माधोटांडा थाने पहुंचे। उन्होंने थाने का घेराव कर नारेबाजी की और पुलिस के खिलाफ रोष जताया। संगठनों ने नामजद शिकायत दर्ज कराई तथा इसे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर हमला बताया। इस दौरान ठाकुर शिवम सिंह भदौरिया, ठाकुर बृजेश सिंह तोमर, दीपू मौर्य, आकाश पांडे, देवांश चौहान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

थाना अध्यक्ष अशोक पाल ने बताया कि वीडियो वायरल होने पर संज्ञान लिया गया है। आरोपियों की पहचान की जा रही है तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी जल्द जेल के पीछे होंगे।

भानु सप्तमी एवं शबरी जयंती पर इण्डियन हेल्पलाइन सोसाइटी की बृज की रसोई द्वारा निःशुल्क भोजन सेवा का आयोजन

जनसेवा की मिसाल बनी बृज की रसोईं ` सैकड़ों जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन, सामाजिक समरसता का सशक्त संदेशः रामकुमार दोहरे

लखनऊ में इण्डियन हेल्पलाइन सोसाइटी द्वारा जनकल्याणकारी सेवा कार्यक्रम का आयोजनः आर डी वर्मा

(जीएनएस)।

लखनऊ। प्रेरणास्रोत बाबा नीम करौली जी की कृपा एवं आशीर्वाद से इण्डियन हेल्पलाइन सोसाइटी (रजि.) द्वारा संचालित सेवा प्रकल्प बृज की रसोई के अंतर्गत आशियाना, लखनऊ में प्रत्येक रविवार की भांति इस रविवार भी निःशुल्क पौष्टिक भोजन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भानु सप्तमी एवं शबरी जयंती के पावन अवसर पर सामाजिक दायित्व एवं सेवा भाव के साथ संपन्न हुआ। संस्था के संस्थापक विपिन शर्मा ने अवगत

कराया कि कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद नागरिकों, बच्चों, वृद्धजनों एवं असहाय वर्ग को सुव्यवस्थित एवं गरिमामयी वातावरण में पौष्टिक भोजन वितरित किया गया। संस्था का उद्देश्य समाज के वंचित एवं उपेक्षित वर्ग तक पोषणयुक्त आहार पहुँचाना, मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करना तथा सामाजिक समरसता को सशक्त बनाना है। संस्था प्रतिनिधि आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि आज का निःशुल्क भोजन वितरण सॉई मंदिर, सेक्टरझजे, आशियाना से प्रारंभ होकर सेक्टरझएम रिक्शा कॉलोनी, डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पास, नगर निगम जोनझ8 की मलिन बस्तियाँ, तथा श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर (गुलमोहर पार्क, संगम विहार, सेक्टरझएच) सहित अनेक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ विकास पाण्डेय ने बताया कि इस सेवा अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर सैंकड़ो लोगों को संस्था के पदाधिकारियों एवं स्वयंसेवकों द्वारा सप्रेम भोजन परोसा गया। जालिम सिंह ने कहा सेवा का उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग तक पोषणयुक्त आहार पहुँचाना एवं मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करना रहा। कार्यक्रम में जालिम सिंह, आर डी वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामकुमार दोहरे, राजीव पटेल (प्लाई ट्रेडर्स), संजय श्रीवास्तव, विशाल सक्सेना, आशीष श्रीवास्तव, अनुराग दुबे, विकास पाण्डेय, दिनेश पाण्डेय, मुकेश कनौजिया, रामचंद्र, दिव्यांश शर्मा, गोविन्द सिंह ठाकुर, ध्रुव सक्सेना सहित अनेक समाजसेवियों की सक्रिय सहभागिता रही, जिससे सेवा कार्यक्रम अनुशासित एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। संजय श्रीवास्तव ने बताया स्थानीय नागरिकों एवं सामाजिक संगठनों ने संस्था के इस सेवा कार्य की प्रशंसा करते हुए इसे मानवता के प्रति समर्पित अनुकरणीय प्रयास बताया। संस्था के विशाल सक्सेना ने स्पष्ट किया कि इण्डियन हेल्पलाइन सोसाइटी (रजि.) भविष्य में भी इसी प्रकार के जनकल्याणकारी, सामाजिक एवं मानव सेवा कार्यक्रमों को निरंतर, नियमित एवं संगठित रूप से संचालित करती रहेगी।

पीलीभीत में भगवान राम पर आपत्तिजनक वीडियोः हिंदू संगठनों में आक्रोश, आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग

(जीएनएस)।

पीलीभीत, जनपद के बिलसंडा थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो साझा करने का मामला सामने आया है। इस घटना से हिंदूवादी संगठनों में गहरा आक्रोश फैल गया है और क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

बिलसंडा थाना क्षेत्र के ग्राम मकरंदपुर निवासी अमित पुत्र रामचंद्र पर आरोप है कि उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल से भगवान राम के विरुद्ध अभद्र टिप्पणियों वाला वीडियो अपलोड किया। यह वीडियो व्हाट्सएप ग्रुपों और फेसबुक पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे हिंदू समुदाय में भारी नाराजगी है।

विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। उनका कहना है कि यह पोस्ट धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सामाजिक विद्वेष फैलाने का प्रयास है। संगठनों ने चेतावनी दी कि कठोर कार्रवाई न होने पर वे सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

बिलसंडा थाना अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि आरोपी की पहचान अमित के रूप में हो चुकी है। सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी जुटाई जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने का भरोसा दिलाया।

रूस में महीनों से फंसे पीलीभीत के 6 युवक सकुशल लौटे, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के प्रयास रंग लाए

परिजनों की गुहार पर शुरू हुई पहल – लोकेशन ट्रेस कर जारी हुए टिकट, दिल्ली से बीसलपुर तक हुआ भव्य स्वागत

(जीएनएस)।

बीसलपुर/पीलीभीत। रूस में कई महीनों से फंसे पीलीभीत जिले के छह युवकों की सकुशल स्वदेश वापसी से उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। परिजनों ने इसके लिए पीलीभीत के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद से गुहार लगाई थी। यह प्रार्थना पत्र किसान नेता देव स्वरूप पटेल के माध्यम से 22 जनवरी को पूरनपुर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान सौंपा गया था।

बताया गया कि युवकों को दिल्ली के किस एजेंट के माध्यम से रूस भेजा गया था, इसकी स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं थी। यही कारण रहा कि रूस में उनकी सही लोकेशन पता करने में काफी कठिनाई आई। युवकों के मोबाइल फोन रिचार्ज न होने और रहने के स्थान से वाई-फाई हट जाने के कारण संपर्क भी लगभग टूट गया था। जैसे-तैसे नेटवर्क मिलने पर युवकों ने अपनी पीड़ा से जुड़े ऑडियो व वीडियो संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से किसान नेता देव स्वरूप पटेल को भेजे।

इन साक्ष्यों के आधार पर केंद्रीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने भारत सरकार एवं रूस के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क कर युवकों की सही लोकेशन ट्रेस कराई और उनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए आवश्यक निर्देश जारी कराए।

देव स्वरूप पटेल ने बताया कि

पीलीभीत जनपद के राजा बाबू पासवान, छोटेलाल पासवान (महद खास), गिरीश कुमार राजपूत (खगाई), महेश पाल राजपूत (लालपुर), तथा रामवीर कश्यप व बेगराज कश्यप (अधकटा, विधानसभा क्षेत्र बरखेड़ा) के लिए रूस से वापसी हेतु फ्लाइट टिकट जारी किए गए। सभी छह युवक 7 फरवरी की शाम 7:30 बजे मास्को से रवाना होकर 8 फरवरी की सुबह 4:00 बजे दिल्ली पहुंचे।

दिल्ली पहुंचने पर देव स्वरूप पटेल ने उन्हें रिसीव किया और दोपहर करीब 3:00 बजे सभी को बीसलपुर लाया गया। यहां समाजसेवी डॉ. प्रथमेश भारद्वाज के आवास पर युवकों का भव्य स्वागत किया गया और एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई।

इस अवसर पर जिला मंत्री भाजपा आयुष मिश्रा, डायरेक्टर चीनी मिल राजू भैया शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष शरद पाल सिंह, नगर अध्यक्ष सौरभ गुप्ता तथा यशवंत सिंह डॉ .प्रथमेश शंकधार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

रूस से सकुशल लौटे युवकों के परिजनों ने इस कार्य के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह तथा पूरे भाजपा परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

एकता की ताकत, हक की लड़ाई–बाराबंकी में ट्रेडर्स यूनियन की ऐतिहासिक बैठक

(जीएनएस)।

बाराबंकी।जिले के रानी लाज बड़ेल में लाइव बर्ड बाराबंकी ट्रेडर्स यूनियन की महत्वपूर्ण बैठक सफलता पूर्वक सम्पन्न हुई, जिसमें बाराबंकी सहित आसपास के जनपदों से बड़ी संख्या में ट्रेडर भाइयों ने भाग लेकर संगठन की एकता और मजबूती का दमदार संदेश दिया। बैठक में ट्रेडर एसोसिएशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने संगठन को एक बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि ट्रेडर से जुड़े हितों की रक्षा तभी संभव है जब सभी ट्रेडर एक मंच पर खड़े हों और आपसी तालमेल के साथ आगे बढ़ें।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिखराव नहीं, एकता ही संगठन की असली ताकत है।यूनियन के उपाध्यक्ष रंजीत सिंह और गौरव सिंह ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की अपील की।महामंत्री इजहार एवं अफताब ने ट्रेडर भाइयों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाते हुए कहा कि यूनियन हर परिस्थिति में अपने सदस्यों के साथ खड़ी रहेगी। इस दौरान यूनियन के कोषाध्यक्ष राहुल सिंह ने भी अपने संबोधन में पारदर्शिता,आपसी विश्वास और संगठन की आर्थिक मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत कोष और ईमानदार व्यवस्था ही यूनियन को लंबे समय तक ताकत देती है, इसके लिए सभी ट्रेडर भाइयों का सहयोग बेहद जरूरी है।

इस अवसर पर बहराइच से आए सम्मानित ट्रेडर साजन भाई और नफीस भाई की गरिमामयी उपस्थिति रही, वहीं बाराबंकी के मुस्लिम ट्रेडर जमीर, सब्बीर, इकबाल, शेरा, उमेर, समीम, कोठी नूरभाई, अब्बु, तालिब, रहमतुल्ला, अनीस और समीर भाई ने भी संगठन को मजबूत और संगठित बनाए रखने का संकल्प लिया। एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी अम्तीश सिंह ने कहा कि यूनियन की आवाज को पूरी मजबूती के साथ शासन-प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा, ताकि ट्रेडर्स की समस्याओं का समय रहते समाधान हो सके। बैठक के अंत में सभी उपस्थित ट्रेडर भाइयों ने एकजुटता, भाईचारे और संघर्ष के साथ यूनियन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प दोहराया, जिससे पूरा माहौल जोश, विश्वास और एकता से गूंज उठा।

पुआल के ढेर के पास जला मिला व्यक्ति का शव, बीसलपुर क्षेत्र में हड़कंप

मदैर्ना गांव के पास सड़क किनारे मिला शव; पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

(जीएनएस)।

बीसलपुर (पीलीभीत)। कोतवाली क्षेत्र के मदैर्ना गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पुआल के ढेर के पास एक अधेड़ व्यक्ति का जला हुआ शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। सुबह खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने सड़क किनारे झुलसी अवस्था में पड़े शव को देखा और तुरंत गांव में सूचना दी। बाद में पुलिस को बुलाया गया।

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मृतक की पहचान गुलैंदा गौटिया निवासी नेमचंद (53 वर्ष) के रूप में हुई है। शव मदैर्ना गांव के प्राथमिक विद्यालय के समीप सड़क किनारे पुआल के ढेर के पास पाया गया।

घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संजीव कुमार शुक्ला पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रगति चौहान और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने भी स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए।

परिजनों के अनुसार, नेमचंद शराब का सेवन करता था और 7 फरवरी की दोपहर करीब तीन बजे घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। पुलिस शुरूआती जांच में आशंका जता रही है कि संभवतः ठंड से बचने के लिए आग जलाते समय यह हादसा हुआ हो, हालांकि अन्य कोणों पर भी जांच जारी है।

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का सही पता चल सकेगा। फिलहाल मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।